

## भारत में सहकारी समितियों की उत्पत्ति और विकास

महेंद्र सिंह शेखावत  
शोध छात्र

डॉ गुरप्रीत कौर  
पर्यवेक्षक  
वाणिज्य विभाग

डॉ अर्जुन मित्तल  
सह पर्यवेक्षक

महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान

### सार

भारत में सहकारिता का इतिहास सौ वर्षों से भी अधिक पुराना है। यहाँ, विशेषतः १९४७ के बाद, सहकारी समितियों का बहुत तेजी से विकास हुआ। एक अनुमान के अनुसार, देश में ६ लाख सहकारी समितियाँ सक्रिय हैं, अरबों लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये समितियाँ अधिकांश समाज में काम कर रही हैं, लेकिन कृषि, उर्वरक और दूध उत्पादन में उनकी भागीदारी सबसे अधिक है। अब बैंकिंग क्षेत्र में सहकारी समितियों की संख्या बढ़ रही है लेकिन देश के सहकारी आन्दोलन कई विसंगतियों के जाल में फँस गए हैं।

भारत में सहकारिता का प्रारंभिक विकास ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। १८६० में, भारत सरकार ने सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए एक कानून पारित किया। इस कानून के बाद, कई कृषि सहकारी समितियों का गठन हुआ। इन समितियों ने किसानों को ऋण, बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने में मदद की।

स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने सहकारिता को देश के आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन माना। सरकार ने सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए। इन उपायों के परिणामस्वरूप, सहकारी समितियों का तेजी से विकास हुआ।

आज, भारत में सहकारी समितियाँ विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं। इनमें कृषि, उद्योग, वित्त, व्यापार और सेवाएं शामिल हैं। सहकारी समितियों ने देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

### मुख्य शब्द

सहकारिता, इतिहास, आर्थिक, विकास

## भूमिका

भारत में सहकारी समितियों की उत्पत्ति और विकास एक लम्बी और विस्तृत प्रक्रिया रही है। सहकारिता के विचारों का भारत में आगमन 18वीं शताब्दी में हुआ, जब यूरोपीय व्यापारियों ने भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इन व्यापारियों ने भारत के किसानों और मजदूरों को सहकारी समितियों के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया।

भारत में सहकारिता का इतिहास सौ वर्षों से भी अधिक पुराना है। यहाँ, विशेषतः १९४७ के बाद, सहकारी समितियों का बहुत तेजी से विकास हुआ। एक अनुमान के अनुसार, देश में ६ लाख सहकारी समितियाँ सक्रिय हैं, अरबों लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये समितियाँ अधिकांश समाज में काम कर रही हैं, लेकिन कृषि, उर्वरक और दूध उत्पादन में उनकी भागीदारी सबसे अधिक है।

भारत में सहकारिता का प्रारंभिक विकास ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, कुछ समाज सुधारकों और उदारवादियों ने लोगों को अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए सहकारिता के सिद्धांतों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इनमें दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे व्यक्ति शामिल थे।

1882 में, मुंबई में एक सहकारी बैंक की स्थापना की गई, जो भारत में पहली सहकारी बैंक थी। इसके बाद, अन्य सहकारी समितियों की स्थापना की गई, जैसे कि कृषि सहकारी समितियाँ, उर्वरक सहकारी समितियाँ और दूध सहकारी समितियाँ।

स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए। 1952 में, भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना की, जो सहकारी समितियों को वित्त और प्रौद्योगिकी सहायता प्रदान करता है।

1950 के दशक में, भारत सरकार ने सहकारी समितियों को कृषि और ग्रामीण विकास के लिए एक प्रमुख एजेंट के रूप में देखा। इस अवधि के दौरान, कई कृषि सहकारी समितियों और ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना की गई।

1960 के दशक में, भारत सरकार ने सहकारी समितियों को औद्योगिकीकरण और ग्रामीण विकास के लिए एक प्रमुख एजेंट के रूप में देखा। इस अवधि के दौरान, कई सहकारी औद्योगिक उपक्रमों और सहकारी ग्रामीण विकास बैंकों की स्थापना की गई।

आज, भारत में सहकारी समितियों का एक व्यापक नेटवर्क है। ये समितियाँ विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं, जैसे कि कृषि, उद्योग, वित्त, वितरण और उपभोक्ता सेवाएं।

सहकारी समितियों ने भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन समितियों ने लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद की है और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा दिया है।

सहकारी समितियां आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। वे किसानों, श्रमिकों और अन्य कमजोर वर्गों को वित्त, कृषि उत्पादों के विपणन और अन्य सहायता प्रदान करके उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद करती हैं।

सहकारी समितियां सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। वे सभी सदस्यों को समान अवसर प्रदान करते हैं, भले ही उनकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो।

सहकारी समितियां ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे किसानों को उनकी कृषि उत्पादकता बढ़ाने, कृषि उपकरणों और अन्य संसाधनों तक पहुंच प्रदान करने और कृषि उत्पादों के बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद करते हैं।

सहकारी समितियां स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करके सदस्यों के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार करने में मदद करती हैं।

भारत में सहकारी समितियों के भविष्य के लिए संभावनाएं उज्ज्वल हैं। सरकार के समर्थन और सदस्यों की भागीदारी के साथ, सहकारी समितियां देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

भारत में सहकारी समितियों की उत्पत्ति और विकास

सहकारी समितियां सभी लोगों, विशेष रूप से कमजोर समूहों को समान अवसर प्रदान करती हैं। वे गरीबी और असमानता को कम करने में मदद करते हैं। सहकारी समितियां सदस्यों के स्वामित्व और नियंत्रण पर आधारित होती हैं। यह उन्हें अपने स्वयं के समुदायों की बेहतरी के लिए भाग लेने का अवसर प्रदान करता है। भारत में सहकारी समितियां कृषि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे किसानों को ऋण, बीज, उर्वरक और अन्य कृषि उपकरण प्रदान करती हैं। वे कृषि उत्पादों के विपणन और मूल्य संवर्धन में भी मदद करते हैं।

सहकारी समितियां लोगों को बचत करने, ऋण लेने और संपत्ति बनाने के लिए एक मंच प्रदान करती हैं। वे विशेष रूप से छोटे व्यवसायों और कमजोर समूहों के लिए महत्वपूर्ण हैं। सहकारी समितियां उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं को कम कीमतों पर उपलब्ध कराती हैं। वे सदस्यों को अपने स्वयं के व्यवसायों को चलाने का अवसर भी प्रदान करते हैं। भारत सरकार ने सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां और कार्यक्रम लागू किए हैं। इन नीतियों और कार्यक्रमों का उद्देश्य सहकारी समितियों को अधिक प्रभावी बनाने और उन्हें आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय में योगदान करने में मदद करना है।

भारत में सहकारी समितियों के विकास के प्रमुख चरण निम्नलिखित हैं

प्रारंभिक चरण (18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य)

इस चरण में, भारत में सहकारी समितियों का विकास यूरोपीय व्यापारियों के प्रयासों से हुआ। इन व्यापारियों ने भारत के किसानों और मजदूरों को सहकारी समितियों के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया।

विकास चरण (19वीं शताब्दी के मध्य से 1947)

इस चरण में, भारत में सहकारी समितियों का विकास भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयासों से हुआ। कांग्रेस ने भारत में सहकारिता को एक आर्थिक और सामाजिक आंदोलन के रूप में बढ़ावा देने का काम किया।

विस्तार चरण (1947 से आज तक)

स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार ने सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए। इन उपायों के परिणामस्वरूप, भारत में सहकारी समितियों का तेजी से विकास हुआ।

भारत में सहकारी समितियों के विभिन्न प्रकार हैं। इनमें से कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं

कृषि सहकारी समितियां ये समितियां किसानों को ऋण, बीज, उर्वरक और अन्य कृषि उपकरण उपलब्ध कराती हैं।

उद्योग सहकारी समितियां ये समितियां विभिन्न प्रकार के उद्योगों में काम करती हैं।

वित्तीय सहकारी समितियां ये समितियां सदस्यों को बचत और ऋण सेवाएं प्रदान करती हैं।

व्यापार सहकारी समितियां ये समितियां कृषि उत्पादों, उपभोक्ता वस्तुओं और अन्य वस्तुओं का व्यापार करती हैं।

सेवा सहकारी समितियां ये समितियां विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सेवा और परिवहन सेवा।

भारत में सहकारी समितियों के कई महत्व हैं। इनमें से कुछ प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं

आर्थिक विकास सहकारी समितियां देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे किसानों, श्रमिकों और अन्य कम आय वाले लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं।

सामाजिक न्याय सहकारी समितियां सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। वे सभी लोगों, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, को समान अवसर प्रदान करती हैं।

विकासशील क्षेत्रों का विकास सहकारी समितियां विकासशील क्षेत्रों के विकास में मदद करती हैं। वे इन क्षेत्रों में लोगों को रोजगार और आय के अवसर प्रदान करती हैं।

भारत में सहकारी समितियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियां निम्नलिखित हैं वित्तीय अस्थिरता कई सहकारी समितियां वित्तीय अस्थिरता का सामना कर रही हैं।

अकुशलता और भ्रष्टाचार कुछ सहकारी समितियों में अकुशलता और भ्रष्टाचार की समस्या है।

सरकारी हस्तक्षेप सरकार की ओर से अत्यधिक हस्तक्षेप सहकारी समितियों के विकास में बाधा डाल रहा है।

भारत में सहकारी समितियों ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, इन समितियों के सामने कई चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है

प्रशासनिक चुनौतियां सहकारी समितियों के प्रशासन में अक्सर अकुशलता और भ्रष्टाचार की समस्या होती है। इससे समितियों का विकास प्रभावित होता है।

वित्तीय चुनौतियां सहकारी समितियों को अक्सर पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की कमी होती है। इससे इन समितियों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाई होती है।

प्रशासनिक चुनौतियां सहकारी समितियों के सदस्यों के बीच अक्सर मतभेद और संघर्ष होते हैं। इससे समितियों का संचालन प्रभावित होता है।

प्रतिस्पर्धा की चुनौतियां सहकारी समितियों को निजी क्षेत्र की कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इससे इन समितियों को बाजार में अपना स्थान बनाए रखना मुश्किल होता है।

इन चुनौतियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं

प्रशासनिक सुधार सहकारी समितियों के प्रशासन में सुधार के लिए, इन समितियों के लिए कड़े नियम और विनियम बनाए जाने चाहिए। इसके साथ ही, इन समितियों के कर्मचारियों और अधिकारियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

वित्तीय सहायता सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, सरकार को इन समितियों को ऋण और अनुदान देने की योजनाएं शुरू करनी चाहिए।

सदस्यों के बीच एकता सहकारी समितियों के सदस्यों के बीच एकता बढ़ाने के लिए, इन समितियों में सदस्यों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना सहकारी समितियों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, इन समितियों को नवाचार और आधुनिकीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

इन उपायों को लागू करने से भारत में सहकारी समितियों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।

भारत में सहकारी समितियों की कुछ विशिष्ट चुनौतियों पर एक नजर डालते हैं

वित्तीय सहकारी समितियों ग्रामीण क्षेत्रों में, वित्तीय सहकारी समितियां किसानों और ग्रामीण लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सेवा प्रदाता हैं। हालांकि, इन समितियों को अक्सर अपर्याप्त पूंजी, अकुशल प्रबंधन और सरकारी हस्तक्षेप जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

कृषि सहकारी समितियां कृषि सहकारी समितियां किसानों को कृषि उत्पादों के उत्पादन और विपणन में मदद करती हैं। हालांकि, इन समितियों को अक्सर बाजार की प्रतिस्पर्धा, अकुशल प्रबंधन और सरकारी हस्तक्षेप जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

उपभोक्ता सहकारी समितियां उपभोक्ता सहकारी समितियां उपभोक्ताओं को खाद्य और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करती हैं। हालांकि, इन समितियों को अक्सर प्रतिस्पर्धी बाजार, अकुशल प्रबंधन और सरकारी हस्तक्षेप जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

इन चुनौतियों को दूर करने के लिए, भारत सरकार को सहकारी समितियों के लिए एक मजबूत नीति और समर्थन प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है। इससे सहकारी समितियों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करने में मदद मिलेगी।

निष्कर्ष

भारत में सहकारी समितियां एक महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक शक्ति हैं। वे देश के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार और सहकारी समितियों को मिलकर काम करने की जरूरत है।

संदर्भ

- भारत में सहकारिता का विकास एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, एम. एस. गुप्ता, भारतीय सहकारी साहित्य प्रकाशन, 2019
- भारतीय सहकारिता में ऋण सहकारिता का विकास, पी. के. पांडेय, सहकारिता पत्रिका, 2018
- भारत में सहकारिता का आधुनिक विकास, एन. एस. शर्मा, सहकारिता पत्रिका, 2019
- भारत में सहकारिता के विकास में चुनौतियां और संभावनाएं, जे. पी. श्रीवास्तव, सहकारिता पत्रिका, 2018
- भारत में सहकारिता का भविष्य, पी. के. शर्मा, सहकारिता पत्रिका, 2015
- सहकारिता का विकास, जे. पी. श्रीवास्तव, 2018
- सहकारिता सिद्धांत और व्यवहार, पी. के. शर्मा, 2015